



अमर भास्कर

उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखण्ड में प्रसारित

ज़िद सच की



उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले- असफलता से०।

Email- amarbhaskar21@gmail.com, www.amarbhaskar.in

यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सुधार की०।

वर्ष: ०२ अंक: १३५

बदायूँ, सोमवार ०२ दिसंबर २०२४

पृष्ठ- ०८

मूल्य- ४.०० रुपये

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले-

असफलता से सीख लेंगे तो होंगे कामयाब

कानपुर। आप बच्चों को संकल्प लेना होगा। उनमें ज्ञान की जिजासा, माता पिता के प्रति सम्मान, शिक्षकों के प्रति आदर होना चाहिए। यह छात्र जीवन कभी वापस नहीं आएगा। आप लोग जिजासा रखें। आपके मन में करियर के लिए जो भी हो उस ओर कार्य करें। अगर आप खेल में जाना चाहते हैं तो जाएं। आपका मन जिस ओर है उस तरफ़ कार्य करें। समाज में जो विकार हैं उसको हटाने का एकमात्र साधन शिक्षा है। हर व्यक्ति को इसलिए शिक्षा का अधिकार दिया गया है।



से सीख ले ली है तो आप जरूर समाज में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हमारे मन में सदा रहना चाहिए अपील करता हूँ कि आप रिसर्च कि भारत जैसा कोई दूसरा देश और अंडे डेवलेपमेंट पर खर्च करें। यह नहीं है। आप बहुत ही भाग्यशाली बातें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। भारत किसी का मोहताज नहीं ने कही। वह रविवार को से थे और जैसा कोई ग्रोथ आठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल के प्रतिशत हो गई है। सुन्देर बढ़ा अच्छा स्वर्ण जयंती संस्थापक दिवस लग रहा है कि आज जयपुरिया

परिवार के सभी लोग उपरिथत हैं। उपराष्ट्रपति ने औद्योगिक घरानों में पौधारोपण से शुरूआत की। निवेश करने की अपील की। स्कूल के हेड बॉर्ड, हेडगार्ल और विभिन्न हाउस के हेड बॉर्ड व गर्ल के साथ फोटो खिंचाई। राष्ट्रगान के साथ दीप प्रज्वलन हुआ। उपराष्ट्रपति ने नए भारत के निर्माण राष्ट्रपति के इस्तेमाल करें, जिससे फंड का इन्सेमाल करें, जिससे शिक्षा मिल सके। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, विधान सभा में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने देश के युवाओं की क्षमता, ज्ञान और कौशल के माध्यम से इस क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता के बारे में बात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राष्ट्र निर्माण के लिए प्रगतिशील दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए जयपुरिया स्कूल की प्रशंसन की।

एक नजर

वीडियो से संसद पृष्ठ यादव को फिर मिली धमकी

पटना। पूर्णिया सांसद पृष्ठ यादव को इस बार खुले आम धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने वीडियो जारी कर पांच से छह दिनों में सांसद की हत्या का दावा किया है। वीडियो जारी कर युवक ने कहा कि लैंगिंस बिश्नोई गैंग, पूर्णिया के सांसद पृष्ठ यादव का कल्प अगले पांच से छह दिनों में करने जा रहा है। वीडियो व्हाट्सएप नंबर (748040395) से सांसद को भेजा गया है। इसमें धमकी देने वाले को ऑर्डर मिला है। हमलोग बहुत जल्द पृष्ठ यादव की हत्या कर देंगे। हमलोग पटना पहुँच चुके हैं। इससे पहले शुक्रवार को भी उन्हें अधिकारी 24 घंटे तक मजा करने की महौलत दी थी। धमकी में लिखा गया था कि अधिकारी 24 घंटे हैं पृष्ठ यादव तो यापा। एक धमाके का वीडियो भी व्हाट्सएप पर पृष्ठ यादव को भेजा गया था। इसके बाद धमकी देने वाले ने पृष्ठ यादव को लिखा था कि गार्ड भी तुम्हें नहीं बचा पाएँगे। इतना ही नहीं धमकी देने वाले ने युद्ध को लैंगिंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए सात सेकेंड का धमाके से जुड़ा एक वीडियो भी भेजा।

सीएम का नाम तय, बस शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार, पूर्व मंत्री बोले लोग उनसे वाफिक



मुंबई। भाजपा नेता रावसाहेब दानवे ने रविवार को अपने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है और अब बस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी का इंतजार है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे ने कही कि किसी का नाम लिए बिना कहा कि महाराष्ट्र के लोग जानते हैं कि अगला सीएम कौन होगा। गोरतलब है कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि महायुति सरकार का शपथ प्रग्रहण समारोह पांच दिसंबर को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पर होगा। हालांकि बावनकुले ने ये नहीं बताया कि सीएम पद की शपथ

अचानक से अपने सतारा स्थित गांव पहुँचे, उसके बाद अटकतों का दौर शुरू हो गया। ऐसा कहा गया कि एकनाथ शिंदे नई सरकार के गठन से खुश नहीं हैं। अपने गांव पहुँचकर शिंदे की तबीयत भी खबाब हो गई। हालांकि अब शिंदे के रविवार शाम तक मुंबई लौटें की चाचा हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार, महाराष्ट्र के अगले सीएम की रेस में देवेंद्र फणवीस का नाम सबसे आगे है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही देवेंद्र फणवीस की ताजोपेशी हो जाएगी, लेकिन दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र

फणवीस सीएम पद की रेस में थे, लेकिन कुछ दिन पहले एकानाथ शिंदे ने भी एसे संकेत दे दिए थे कि उन्हें भाजपा की मुख्यमंत्री मंजूर है। उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि जल्द ही देवेंद्र फणवीस की शामिल की जाएगी। द्वारा उन नेतों के नाम को मंजूरी दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में किस-किस को शामिल किया जाएगा?

प्रजनन दर २.१ से नीचे नहीं जानी चाहिए, मोहन भागवत ने जताई चिंता

दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए बताया कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) २.१ से नीचे चला जाता है तो वह समाज धीरे-धीरे पृथकी से लुप्त होने की कगड़ी है। संकट न होने पर भी वह समाज नहीं हो जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) २.१ से नीचे नहीं जानी चाहिए। हाथों देश की जनसंख्या नीति १९९८ या २००२ में तय की गई थी। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या २.१ से कम नहीं होनी चाहिए। जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें दो या तीन से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है।

अमर भास्कर, ब्लू

संभल। जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम ने रविवार को हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने जिलाधिकारी, एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ जामा मस्जिद सहित उन सभी स्थानों का गहन निरीक्षण किया,

जहां हिंसा और पथराव हुआ था। इस घटना में पांच लोगों की मौत हो गई थी और १९ पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उधर, पूर्व डीजीपी और तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्य एक जैन ने कहा कि 24 नवंबर को शाही मस्जिद इलाके में पहुँची। जामा मस्जिद इलाके के दौरान टीम ने मस्जिद के बाहर और दुकानदारों और निवासियों से बातचीत की। दुकानदारों ने कहा कि कोटर्गांव से शुरू हुआ विवाद

पर थराव के दौरान उन्होंने अपनी जामा मस्जिद की तह तक पहुँची। आयोग की टीम सबसे पहले धीरे-धीरे बवाल में बदल गया।

उधर, पूर्व डीजीपी और तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग के सदस्य एक जैन ने रविवार को बताया कि कोटर्गांव से शुरू हुआ विवाद

पर थराव के दौरान उन्होंने अपनी जामा मस्जिद के बाहर और निवासियों से बातचीत की। दुकानदारों ने कहा कि कोटर्गांव से शुरू हुआ विवाद

पर थराव के दौरान उन्होंने अपनी जामा मस्जिद के बाहर और निवासियों से बातचीत की। दुकानदारों ने कहा कि कोटर्गांव से शुरू हुआ विवाद

पर थराव के दौरान उन्होंने अपनी जामा मस्जिद के बाहर और निवासियों से बातचीत की। दुकानदारों ने कहा कि कोटर्गांव से शुरू हुआ विवाद

महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार जस्टिस चंद्रचूड़ हैं

पूर्व सीजेआई पर भड़के संजय रात



मुंबई। महाराष्ट्र चुनाव नीतीजे को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय रात ने गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर थीकरा फेंड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव नीतीजों को सविधान के खिलाफ बताया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। चुनाव नीतीजे थोकित हुए एक राज्यपाल के द्वारा नहीं हैं कि हिमाकत नहीं करता। इतिहास हार के लिए संजय रात ने पहली इसके बारे में बोला है। और अभी तक महाराष्ट्र में सीधे कोर्ट के नाम का एलान नहीं हुआ है। इस पर शिवसेना यूबीटी को आरोप लगा गया। संजय रात ने कहा कि महाराष्ट्र चंद्रचूड

संपादकीय

जलवायु वित्त पर असहमति



अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित कांग्रेस ऑफ पार्टीज (कॉप२१) की 29वीं बैठक एक ऐसी जलवायु वित्त बैठक के रूप में आयोजित हुई जहां ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सवन कारने वाले विकासित देश विकासशील देशों के जलवायु अनुकूलन और उत्सर्जन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए २०२५ के आगे की नई वित्तीय प्रतिबद्धता तय करने वाले थे। परंतु तीव्र बहस के उपरान रविवार को जब तय अवधि के दो दिन बाद जब यह बैठक समाप्त हुई तब वह एक ऐसे वित्तीय समझौते पर पहुंची, जिसका भारत, नाइजीरिया, बोलिविया और क्यूबा ने चोर विरोध किया।

इसके अलावा जितनी राशि की प्रतिबद्धता जारी गई उसके विरोध में छोटे द्विपक्षी देशों के समूह तथा जलवायु संकट झेल रहे अन्य देशों ने आयोजन का बहिष्कार भी किया। हालांकि नए समग्र मात्रात्मक लक्ष्य (एनसीव्यूजी) के अंतर्गत २०३५ तक सालाना ३०० अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जारी गई है जो पहले जारी गई सालाना १०० अरब डॉलर की प्रतिबद्धता से काफ़ी अधिक है। लेकिन यह विकासशील देशों की १.३ लाख करोड़ डॉलर की मांग से काफ़ी कम है।

इस तमाम असंतोष के बीच वार्ताकारों ने संकेत दिया है कि समझौता चाहे जितना भी अपूर्ण हो, परंतु नहीं होने से तो वह बहर ही होता है। महज दो माह पहले कॉप२१ के पाले बाकू में वार्ताकारों की बैठक में सरकार देश एनसीव्यूजी के अधीन किसी वित्तीय प्रतिबद्धता पर नहीं पहुंच पाए थे। परंतु जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील देशों के पास इस बात की अच्छी-खासी वजह है कि वे बाकू में हुए समझौते को लेकर मजबूत पूर्वग्रह रखें।

आगे मौजूदा रुझानों को मानक माना जाए तो ३०० अरब डॉलर की अपेक्षा राशि जुटा पाना भी मुश्किल नजर आ रहा है। पहले जलवायु वित्त लक्ष्य के लिए १०० अरब डॉलर की राशि तय की गई थी। इस राशि पर कोपनहेगन में २००९ में आयोजित कॉप१५ में सहमति बनी थी। इस लक्ष्य को २०२२ में यानी केवल एक बार हासिल किया जा सका था वह भी लक्षित वर्ष के दो बार। दूसरी बात यह कि अधिक वित्तीय सहयोग की मांग भी अस्पृश है। उत्तरार्थ के लिए कॉप१५ में बाकू से बैलोम खाके पर सहमति बनी। ब्राजील के बैलोम शहर में अगले वर्ष कॉप१० का आयोजन होना है। वहां सभी पक्ष साथ मिलकर 'सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों' का इस्तेमाल करके २०३५ तक सालाना १.३ लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

योजना यह है कि २०३० तक इस निर्णय पर नजर रखी जाए। इस बीच २०२६ और २०२७ में रिपोर्ट आएंगी। आखिर में समझौता विकासशील देशों से आग्रह करता है कि वे इस लक्ष्य को पाने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहयोग करें। यह वैश्विक समृद्ध देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ के दायित्वों में महत्वपूर्ण कमी करने वाली बात है। एक सकारात्मक बात यह है कि करीब एक दशक की बातचीत के बाद कॉप २१ में करीब २०० देश इस बात पर सहमत हुए कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद ६ के अधीन कार्बन बाजार के संचालन की दिशा में बढ़ा जाए। इसके बाद दो देशों के बीच व्यापार और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के पूरी तरह काम करने की उम्मीद है। कार्बन ट्रेडिंग जलवायु वित्त का एक अहम स्वरूप है और ये नियम भारत को इस बाजार को परिचालित करने में मदद करेंगे। भारत को उपर कार्बन कार्बन द्वारा समझौते को नकारने तथा दुनिया के गरीब देशों की दिमाग़त करने का लाभ मिला है। परंतु तथ्य यह है कि विकासशील देशों की आपत्तियों को आसानी से खारिज कर दिया गया। यह बताता है कि इन वार्ताओं में काफ़ी असमानता है और ऐतिहासिक दायित्व से पीछे हट रहे हैं। जलवायु संकट को शाक की दृष्टि से देखने वाली ट्रांप सरकार के आगमन के बाद यह रुझान और बढ़ेगा। ट्रांप अपने पहले कार्यकाल में पेरिस समझौते को नकार चुके हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि बाइडन प्रशासन के ठोस इरादों के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस लगातार जलवायु वित्त अनुरोधों पर उसे नकारती रही।

अमर भास्कर

(हिन्दी दैनिक समाचार पत्र)

- वरिष्ठ संरक्षक : वेदभानु आर्य
- संरक्षक : हमिद अली खाँ
- संरक्षक : सुरेश प्रसाद शर्मा
- प्रधान संपादक : फरीद क्रादरी
- संपादक : अबरार अहमद
- कानूनी सला : मुहम्मद फुरकान, एड.
- व्यवस्थापक : ठा. वेदपाल सिंह
- मैनेजर : केपी यादव
- सह-संपादक : मोहम्मद राशिद

हमारे यूट्यूब चैनल Amar Bhaskar News को सब्सक्राइब करें वैल आइकॉन दबाना न भूलें।

- सर्वें उपाध्याय, मैनेजरिंग एडिटर*

अगर आपके पास भी है कोई कविता, रचना, लेख, गजल एवं छंद तो हमें लिख भेजिए, हमारा पता है:-

अमर भास्कर कार्यालय

निकट होटल रिजेन्सी, लालेला चौक बदायूं (उ.प्र.)।

पिन कोड- 243601

Email- amarbhaskar21@gmail.com

Whatsapp. No. 9411214614

विवादों के बादल, अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा

आखिर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। करीब ढाई महीने पहले अकाली दल तत्कालीन लक्ष्यों की आरोपी वित्तीय प्रतिबद्धता को बातचीत की जाए तो उन्होंने २०१८ में पिता प्रकाश सिंह बादल के हाथों से पार्टी की कमान ली थी। इन्हें दशकों में थीरे-थीरे पार्टी का ग्राफ़ नीचे ही आता रहा।

पिछले करीब तीन दशकों में यह पहला मौका है जब शिरोमणि अकाली दल के टॉप पर बादल परिवार को कोई सदस्य नहीं है। खुद सुखबीर बादल की बात की जाए तो उन्होंने २०१८ में पिता प्रकाश सिंह बादल के हाथों से पार्टी की कमान ली थी। इन्हें दशकों में थीरे-थीरे पार्टी का ग्राफ़ नीचे ही आता रहा।



के २७.५ प्रतिशत से घटकर १३.४: राजनीति में एक ऐसे नए खिलाड़ि पर आग आया और इसे राज्य की कुल १३ लोकसभा सीटों में साम्राज्य का उद्भव हुआ, जिसने प्रदेश के सीटों पर कामरिक राजनीतिक स्वरूप को बदल कर रख दिया। जाहिर है, आम आदमी पार्टी के रूप में प्रदेश अकाली दल के सामने अस्तित्व को सुधार लहर के रूप में असंतुष्टों का

बनाए रखने की चुनौती है। ऐसे में एक ऐसा ग्रुप पार्टी में उभर आया है, जो उनकी राह में लगातार मुश्किलों विरुद्ध कर रहा था।

हालांकि पार्टी में चल रहे इस सीमावर्ती राज्य के लिए खासे अहम आंतरिक संघर्ष को अभी किसी साकत हो सकते हैं।

सुधार की जरूरत, यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी पुलिस को जैसी कड़ी फटकार लगाई है, उससे जाहिर होता है कि मर्ज पुराना है और गंभीर भी देश की शीर्ष अदालत को अगर यहां तक कहना पड़े कि पुलिस पावर का आनंद ले रही है और उसे संवेदनशील होने की जरूरत है, तो इसका मतलब कि खाकी उन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उत्तर पर रही है। यह विकासशील नॉर्थ के दायित्वों में महत्वपूर्ण कमी करने वाली बात है। एक दशक के लिए आरंभी भी कम है। इस लक्ष्य को २०२२ में यानी केवल एक बार हासिल किया जा सका था वह भी लक्षित वर्ष के दो बार। दूसरी बात यह कि अधिक वित्तीय सहयोग की मांग भी अस्पृश है। उत्तरार्थ के लिए कॉप१५ में बाकू से बैलोम खाके पर सहमति बनी। ब्राजील के बैलोम शहर में अगले वर्ष कॉप१० का आयोजन होना है। वहां सभी पक्ष साथ मिलकर 'सभी सार्वजनिक और निजी स्रोतों' का इस्तेमाल करके २०३५ तक सालाना १.३ लाख करोड़ डॉलर के लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करेंगे।

योजना यह है कि २०३० तक इस निर्णय पर नजर रखी जाए। इस बीच २०२६ और २०२७ में रिपोर्ट आएंगी। आखिर में समझौता विकासशील देशों से आग्रह करता है कि वे इस लक्ष्य को पाने के लिए स्वैच्छिक रूप से सहयोग करें। यह वैश्विक समृद्ध देशों यानी ग्लोबल नॉर्थ के दायित्वों में महत्वपूर्ण कमी करने वाली बात है। एक सकारात्मक बात यह है कि करीब एक दशक की बातचीत के बाद कॉप २१ में करीब २०० देश इस बात पर सहमत हुए कि पेरिस समझौते के अनुच्छेद ६ के अधीन कार्बन बाजार के संचालन की दिशा में बढ़ा जाए। इसके बाद दो देशों के बीच व्यापार और कार्बन क्रेडिट प्रणाली के पूरी तरह काम करने की उम्मीद है। कार्बन ट्रेडिंग जलवायु वित्त का एक अहम स्वरूप है और ये नियम भारत को इस बाजार को परिचालित करने में मदद करेंगे। भारत को उपर कार्बन द्वारा समझौते को नकारने तथा दुनिया के गरीब देशों की दिमाग़त करने का लाभ मिला है। परंतु तथ्य यह है कि विकासशील देशों की आपत्तियों को आसानी से खारिज कर दिया गया। यह बताता है कि इन वार्ताओं में काफ़ी असमानता है और ऐतिहासिक दायित्व से पीछे हट रहे हैं। जलवायु संकट को शाक की दृष्टि से देखने वाली ट्रांप सरकार के आगमन के बाद यह रुझान और बढ़ेगा। ट्रांप अपने पहले कार्यकाल में पेरिस समझौते को नकार चुके हैं। यह भी ध्यान देने

अमेरिकी डॉलर की जगह और मुद्रा अपनाई तो लगेगा टैरिफ़: ट्रंप

वाशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके हैं। वह आले साल 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। इस बीच, ट्रंप ने शनिवार को ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों से कहा कि अगर उन्होंने अमेरिकी डॉलर के बजाय कोई और मुद्रा अपनाई तो उन पर 100 प्रतिशत टैरिफ़ लगाया जाएगा।

चेतावनी के साथ ही ट्रंप ने नौ सदस्यीय समूह से प्रतिबद्धता मार्गी है, जिसमें भारत, रूस, चीन और ब्राजील शामिल हैं। ब्रिक्स का गठन 2009 में किया गया था। यह एकमात्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समूह है, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका हिस्सा नहीं है। इसके अन्य सदस्य दिक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमेरिका हैं। पिछले कुछ वर्षों में ब्रिक्स के कुछ सदस्य देश, विशेष रूप से रूस और चीन, अमेरिकी



बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा।

उन्होंने कहा कि जो भी देश ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे अमेरिका को अलविदा कह देगा चाहिए। 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने एक नई आम मुद्रा बनाने की संभावना पर विचार करने का निर्णय लिया। इस विचार का प्रस्ताव ब्राजील के राष्ट्रपति लुडविग इनासियो लूला दा सिल्वा ने रखा था। हालांकि, भारत ने इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाने से इनकार कर दिया। भारत का कहना है कि वह अपनी ब्रिक्स मुद्रा प्रतिबद्धता की आवश्यकता है कि बना रहे हैं। हालांकि, भारत अब तक बनाएंगे, न ही अमेरिकी डॉलर को हिस्सा नहीं रहा है। ट्रंप ने अपने रूस और चीन के इस कदम का बदलने के लिए किसी अन्य मुद्रा सोशल मीडिया में दृश्य सोशल कल का समर्थन करेंगे। अगर वे देश ऐसा पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने करने की सोचते हैं तो उन्हें 100 कहा कि वह विचार कि ब्रिक्स देश लक्ष्य बनाकर अपनी आर्थिक रूप से रूस और चीन, अमेरिकी डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कि इस

लोगों ने की ट्रंप से की रिहाई की मांग

वर्षाशतम। 7 अक्टूबर 2023

को हमास के हमले के साथ शुरू हआ युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इन ढेंग साल के समय में दुनिया ने दोनों देशों को बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

बता दें कि बंधक का बीड़ी जास्ती ने अपने एक और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन को आड़े हाथों लिया है। इस दरअसल, एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि न्यूयॉर्क में रिस्ट्रेक्शन फ़ाइल स्टर रूलरेल हाईट के अवैध प्रवासियों को रखने के एक में न्यूयॉर्क शहर ने उसे 220 मिलियन डॉलर का भुगतान की जगह दिया है। इर होटल का स्वामित्व पाकिस्तान सरकार के पास है। विवेक रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उसकी रिहाई है। इकाइल का राष्ट्रपति रामास्वामी ने इसे उत्पादक राष्ट्रपति रामास्वामी की जगह ले लिया है। उन्होंने इसे पागलगन करार दिया है।

दरअसल, ट्रंप ने दिग्गज

कारोबारी एलन मस्क के साथ ही उसके परिवारों के बीच कई सारी विजें देख ली। इसी सिलसिले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां फलस्तीनी उत्पादी सहूल हमास ने शिरायाको एक इकाइल-अमेरिकी बंधक की बीड़ी जारी किया, जिसमें वह अमे

